

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का निष्पाक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिपा

भारतीय बस्ती

बस्ती 7 मई 2026 गुरुवार

सम्पादकीय

सिनेमा से सत्ता तक विजय

तमिलनाडु में सिनेमा और सिंघासत का खासा प्रभाव रहा है, जहां कई लोकप्रिय अभिनेताओं ने फिल्मी प्रदर्श से निकलकर सत्ता के गलियारों तक का सफर तय किया है। राज्य में अभिनेता से नेता बनने की परंपरा की नींव एमजी रामचंद्रन ने रखी थी। उन्होंने वर्ष 1972 में द्रमुक से अलग होकर अन्नाद्रमुक पार्टी का गठन किया और लंबे समय तक राज्य की सत्ता संभाली। अब तमिल सिनेमा के मशहूर अभिनेता विजय भी उनकी राह पर हैं। उनकी पार्टी टीवीके राज्य विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है।

टीवीके की इस जीत को इसलिए अहम माना जा रहा है कि यह उसका पहला चुनाव था और उसने राज्य के इतिहास में एक बार फिर राजनीति की दिशा बदल दी है। इससे पहले यहां की सिंघासत केवल दो दलों द्रमुक और अन्नाद्रमुक के इर्द-गिर्द केंद्रित रहती थी। हालांकि, विजय की पार्टी को सत्ता मिल पाया है, लेकिन राज्य में उनकी सरकार बननी लगभग तय है। अब देखा होगा कि सत्ता संभालने के बाद वे जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतर पाएंगे।

गौरतलब है कि तमिलनाडु की सिंघासत में एमजी रामचंद्रन के बाद कई फिल्मी सितारों ने कदम रखा, जिनमें जयललिता का नाम सबसे ऊपर है। अभिनेता विजयकांत और कमल हासन ने भी नए दलों का गठन किया, लेकिन उन्हें खास कामयाबी नहीं मिल पाई। इसके अलावा, राजनीकांत ने भी वर्ष 2020 में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का एलान किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने कदम वापस खींच लिए। वहीं, अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को बने हुए लगभग दो साल का ही वक्त हुआ है और पहले ही चुनाव में उसने राज्य की मुख्यधारा के दोनों दलों को कराड़ी शिकस्त देकर शानदार जीत हासिल की है।

विजय को अभिनेता के रूप में जिस तरह की फिल्मों से लोकप्रियता मिली है, उनमें से ज्यादातर व्यवस्था की जटिलताएं हुए उसमें सुधार पर केंद्रित रही हैं। अब यह देखने की बात होगी कि इससे पहले सत्ता पर मजबूत पकड़ रखने वाली द्रमुक की राज्य में शासन और विकास की नीतियों के समांतर अब विजय और उनकी टीवीके को बने हुए राजनीति को कौन-सी नई दिशा देते हैं।

महिलाओं की राजनीति में भागीदारी

देश की सभी पार्टियां राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का एक मत से समर्थन करती हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने के लिए तैयारी फीसद आरक्षण का विधेयक पारित कराने में भी सभी दलों की भूमिका रही। मगर महिलाओं की मुनाईदगी के सवाल पर राजीवदा दिखने वाली लगभग सभी पार्टियां क्या तब तक इस मुद्दे पर दोष पहल नहीं करंगी, जब तक विधायिका में आरक्षण की व्यवस्था व्यवहार में लागू न हो जाए?

आखिर क्या वजह है कि देश में लोकसभा या फिर विधानसभा के लिए जब भी चुनाव होते हैं, तो उसमें पर्याप्त संख्या में महिलाओं को टिकट देने को लेकर ईमानदार इच्छाशक्ति का अभाव दिखता है? गौरतलब है कि चार राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों को उस से जितनी महिलाओं को टिकट दिया गया और उन्हीं जीतने वालीं जो संख्या रही, वह महिला भागीदारी के सवाल पर राजनीतिक दलों के प्रचारित संरोकार के प्रति ईमानदारी को कटघरे में खड़ा करती है।

दरमसत, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में हुए चुनाव के दौरान कुल आठ सौ चौबीस सीटों पर चुनाव हुए। उनमें जीत हासिल करने वाली महिलाओं का अनुपात बेहद कम रहा। नतीजों के मुताबिक, इन पांचों प्रदेशों में कुल पांच फीसद सीटों पर ही महिलाएं चुनी गईं। इन राज्यों में अलग-अलग पार्टियों ने महिलाओं को टिकट देने में भी अपने घोषित संरोकारों के उलट रवैया अपनाया। मसलन, पश्चिम बंगाल में दो सासल सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आने वाली भाजपा ने सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को टिकट दिया, लेकिन उसने सिर्फ तैयारी सीटों पर महिलाओं को मौका दिया था।

जबकि तमिलनाडु कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारी के 291 सीटों में से 52 महिलाओं को टिकट दिया था। नतीजतन, राज्य की कुल सीटों में से सिर्फ दस फीसद महिलाएं जीत सकीं। दूसरी ओर, तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ, जहां सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके 234 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उनमें सिर्फ चौबीस महिलाओं को उम्मीदवार बनाया था। असम में फिर से जीतने वाली भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने 126 सीटों में से केवल छह महिलाओं को टिकट दिया। केरल में जीत हासिल करने वाली यूडीएफ ने सिर्फ दस महिलाओं को मौका दिया।

जाहिर है, तकरीबन सभी पार्टियों में महिलाओं को उम्मीदवार बनाने में कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। हालांकि हाल ही में संसद में परिसीमन विधेयक पारित न होने के संदर्भ में महिला आरक्षण का सवाल चुनावी राजनीति का भी मुद्दा बन आया है और इस मुद्दे पर विधायी दलों पर सवाल उठाए गए। विदंबना यह है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के घोषित दावों के बरक्स टिकट देने के मामले में भाजपा सहित सभी पार्टियों के भीतर इच्छाशक्ति की कमी दिखती है। क्या यही सबसे बड़ी वजह नहीं है कि विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने और एक न्यायपूर्ण संतुलन के लिए आरक्षण की जरूरत पड़ती? महज औपचारिकता पूरी करने के लिए किसी महिला को टिकट देने सा संरोकारों के प्रति ईमानदारी को नहीं दिखाया? ऐसे में जरूरत इस बात की है कि महिला आरक्षण की धारणा को पूरव लागू किया जाए और उसके समांतर सभी राजनीतिक दलों की ओर से महिलाओं को अधिकार के रूप में ज्यादा से ज्यादा असर देने को लेकर ईमानदारी से पहल हो।

हिन्दू भाजपा के साथ, मुस्लिम कांग्रेस की ओर!

—नीरज कुमार दुबे—

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में संपन्न विधानसभा चुनावों के नतीजों ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों के लिए मिला जुला चित्र प्रस्तुत किया है। कुछ राज्यों में पार्टी को निराशा हाथ लगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में उसे उल्लेखनीय सफलता भी मिली। इन चुनावों का एक महत्वपूर्ण पक्ष मुस्लिम उम्मीदवारों का प्रदर्शन रहा, जिसने कई राज्यों में राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दी है। खास तौर पर असम और केरल में कांग्रेस तथा उसके सहयोगी दलों के मुस्लिम प्रत्याशियों ने प्रभावशाली जीत दर्ज कर यह संकेत दिया है कि इन इलाकों का एक महत्वपूर्ण पक्ष मुस्लिम उम्मीदवारों का प्रदर्शन रहा, जिसने कई राज्यों में राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दी है।

केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने दस वर्षों के लंबे अंतराल के बाद सत्ता में वापसी की। राज्य में नुनू गए 35 मुस्लिम विधायकों में से 30 संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा से संबधित हैं। इनमें कांग्रेस के आठ और इंडियन यूनिफ़ॉर्म मुस्लिम लीग के 22 विधायक शामिल हैं। यह परिणाम बताता है कि राज्य में मुस्लिम मतदाताओं में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा पर व्यापक प्रभाव है। इंडियन यूनिफ़ॉर्म मुस्लिम लीग की उम्मीदवार



फातिमा तहलिया की जीत विशेष रूप से चर्चा में रही। उन्होंने कोडिकोड जिले की पेराभा सीट पर माकपा नेता टीपी रामकृष्णन को पांच हजार से अधिक मतों से हराया। इस जीत के साथ वह पार्टी की पहली मुस्लिम महिला विधायक बन गईं। उनकी सफलता को मुस्लिम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

असम में कांग्रेस के उर्फ़िन उम्मीदवारों का प्रदर्शन और भी अधिक प्रभावशाली रहा। पार्टी ने राज्य में 20 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 18 ने जीत दर्ज की।

इसके विपरीत कांग्रेस के अधिकांश गैर मुस्लिम उम्मीदवार हार गए और केवल एक गैर मुस्लिम प्रत्याशी को सफलता मिली। कांग्रेस ने कुल 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम उम्मीदवारों की सफलता पर अत्यंत उंची रही। कांग्रेस के सहयोगी राजीव दल को भी दो सीटों पर जीत मिली, जिनमें एक मुस्लिम उम्मीदवार की थी, जबकि दूसरी सीट अखिल गोर्गाई ने जीती। अखिल गोर्गाई पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा माओवादी गतिविधियों से जुड़े आरोपों की जांच चल रही है। असम में कई सीटों पर कांग्रेस

उम्मीदवारों ने भारी अंतर से जीत दर्ज की। गौरिपुर सीट पर कांग्रेस के अब्दुल सोबहान अली सरकार ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार निजानुर रहमान को 19097 मतों से हराया। जयपुर सीट पर कांग्रेस के आफवाक मोसला ने एआईयूडीएफ नेता सैयद आलम को 109688 मतों के भारी अंतर से पराजित किया। समागुरी में तजिल हुसैन ने भाजपा के अनिल सैकिंगा को 108310 मतों से हराया। इसके अलावा अलापुरा कटलीओडा जैसी सीटों पर भी कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत का अंतर एक लाख से अधिक रहा। इन परिणामों ने यह संकेत दिया कि असम के कई क्षेत्रों में

मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के पक्ष में वोटबूटी से एकजुट हुए।

हालांकि असम में कांग्रेस की इस सफलता के बावजूद एआईयूडीएफ प्रमुख मौलाना बद्रुद्दीन अजमल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एआईयूडीएफ को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अब स्वयं समात हो गई है। अजमल ने यह भी कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बन गई है और यह स्थिति उन्हें दुखी करती है। उनका यह बयान असम की राजनीति में मुस्लिम मतों को लेकर बल रही प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि चुनाव प्रदर्श के दौरान असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उसे 'माओवादी मुस्लिम लीग कांग्रेस' करार दिया था। आखिरकार उनकी बात सही साबित हुई।

वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को केवल दो सीटों पर जीत मिली, लेकिन दोनों सीटें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में थीं। पार्टी ने तुमपुल कांग्रेस की तुलना में अधिक मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। वहीं तमिलनाडु में कांग्रेस ने दो मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिनमें से एक को जीत मिली। इन परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने यह उम्मीदवारों में मुस्लिम समुदाय को साहस की स्थिति अपनाई थी और कुछ खराबों पर उसे हराकर लाभ भी मिला। मत प्रतिशत को आंकड़ें भी

इन चुनावों की राजनीतिक दिशा को स्पष्ट करते हैं। असम में भाजपा को 37.81 प्रतिशत मत मिले, जबकि कांग्रेस को 29.84 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। दूसरी ओर केरल में कांग्रेस और इंडियन यूनिफ़ॉर्म मुस्लिम लीग को मिलाकर कुल 39.80 प्रतिशत मत मिले। इससे यह स्पष्ट होता है कि केरल में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुआ।

बहरहाल, इन विधानसभा चुनावों ने यह संकेत दिया है कि देश की राजनीति में धार्मिक और सामाजिक आधार पर मतदाताओं का कड़ीकरण और अधिक स्पष्ट होना जा रहा है। एक ओर जहां भाजपा को व्यापक रूप से हिंदू मतदाताओं का समर्थन मिला दिखता है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय का युवाव फिलों से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। खासकर असम और केरल में मुस्लिम उम्मीदवारों की उल्लेखनीय सफलता ने कांग्रेस को नई राजनीतिक ऊर्जा दी है। वहीं भाजपा और अन्य दलों द्वारा कांग्रेस पर तुल्यकरण तथा विवेक की राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है और वोट कर दिया है। आगे वाले समय में यह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और अधिक तीव्र हो सकती है, क्योंकि विभिन्न दल अपने अपने सामाजिक आधार को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं।

इंडिया गठबंधन के अस्तित्व को बचाने की बड़ी चुनौती



—अजय कुमार—

भारतीय राजनीति के फलक पर 2026 के विधानसभा चुनाव नतीजों ने एक ऐसी लकीर खींच दी है, जिसने विपक्षी एकजुटता के दावों और इंडियाय गठबंधन के मनीष्य पर गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं। चुनावी मैदान को जो आंकड़े सामने आए हैं, वे न केवल चौंकाते वाले हैं, बल्कि गठबंधन के भीतर की गहरी दरारों और वैचारिक विरोधाभासों को भी पूरी तरह नग्न कर देते हैं। एक तरफ कांग्रेस केरल में यूडीएफ के जरिए सत्ता की हथौड़ी पर खड़ी नजर आ रही है, तो दूसरी ओर तरफ पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में गठबंधन के दो सबसे मजबूत स्तंभों तुमपुल कांग्रेस और यूडीएफ का सत्ता से बेदखल होना पूरे विषय के लिए किसी जवाबत से कम नहीं है। विदंबना देखिए कि केरल में कांग्रेस की जीत उसी वामपंथ की हार की कीमत पर मिल रही है, जो राष्ट्रीय स्तर पर उसके साथ शब्दियाय ब्लॉक में कब्जे से कई। आ मिलाकर चलने का दावा करती है, यह अंतर्विरोध बताता है कि गठबंधन की भी जमीन कितनी दरक चुकी है। ममता बनर्जी और ए.एम.के. स्टालिन जैसे कद्दावर नेताओं की अपने-अपने राज्यों में हार ने इस इलाका को घुसका कर दिया है कि घोषणा दलों का अमेघ फैला अब दरक रहा है। बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ें जमाई हैं और अंततः सत्ता हासिल की है, उसने न केवल सत्ता हासिल की है, उसने न केवल सत्ता हासिल की है, बल्कि पूरे देश में विषय के मनबल को तोड़कर रख दिया है। अब सवाल सिर्फ सत्ता हासिल करने का नहीं रह गया है, बल्कि अस्तित्व को बचाने की एक बेहद कठिन लड़ाई का मत बना रहा है। ममता बनर्जी अब भी एकजुटता का राह जगमगी रही हैं, सांघिया गांधी और खालू गांधी के फलन कॉलस का हवाला देकर यह फताने की कोशिश कर रही हैं कि गठबंधन अभी टूटा नहीं है, लेकिन धरतल पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता का यह कहना कि 'असम हारे नहीं, हमें हराया गया है' और चुनाव आयोगों को खलायतक बनाना, हारी हताशा को ही दर्शाता है।



को याद करते हैं। इसी बंगाल की जमीन पर राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों की फूफड़ाका का हवाला देकर ममता की नीतय पर सवाल उठाए थे। हालांकि, अब नतीजों के बाद राहुल गांधी के सूर बढ़ते हुए हैं। पश्चिम बंगाल और असम के जनघरेलू की खोरीर की बात कर दें और इन्हें लोकतंत्र की हथ्या बला रहे हैं। लेकिन क्या यह हथ्या परिवर्तन केवल राजनीतिक मजबूती है? कांग्रेस के नेता ही अंधीर रंजन चौधरी जैसे नेताओं के बयान पर लगे के स्टैंड से नेत्र नहीं खालें। अंधीर ने स्पष्ट रूप से यह इस्सता विधेयी लहर और श्रमवाय लहर का परिणाम बताया था। गठबंधन की इन खोरीरता का सीधा फलपाय साक्षात्तरी दल को मिल रहा है, जो अब और भी अधिक आत्मकलहक अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं।

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के नतीजों ने एक नई धिंता को जन्म दिया है वह है क्षेत्रीय दलों के सांसदों के टूटने का डर। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सांसदों ने पाला बदला, वही खतरा अब टीएमपीसी और डीएमके को भी मंडरा रहा है। लोअरममा में इन दोनों दलों के पास हा सांसदों का बड़ा आंकड़ है। यदि परिसीमन या यूसीसी (समान नायक संहिता) जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर बीजेपी को रोअनना है, तो इन दलों को अपने कुमये को विखरने से बचना होगा। लेकिन सत्ता हाथ से जाने के बाद विधायकों और सांसदों को एकजुट दिखाना किसी हिमायती चुनौती से कम नहीं है। क्षेत्रीय राजनीति का दरवाजा जो कभी भारतीय राजनीति की पहचान हुआ करता था, अब सिमटता जा रहा है। बिहार, दिल्ली और अब बंगाल-तमिलनाडु के उदाहरण बताते हैं कि मतदाता अब रडबल उन्मत्त या एक एजन्त केंद्रीय नयंत्रण की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं।

वोट चोरी पर राजनीतिक चुप्पी क्यों?

—संजय सक्सेना—

भारत की पवित्र भूमि सर्वद सत्तों, सभुओं और महायागों की बरहोर रही है। हर काने में ऐसे पराक्रमी पुष्य और नारियां जन्म लेती रही हैं जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया। अंग्रेजी राज के विरुद्ध महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों की बाजी लगा दी। आजादी के बाद भी जब सत्ता के नेत्रों को संरोकार तानाशाही का रज दिखाने लगी, तब लोकनायक जयप्रकाश नारायण 'होली' जैसे योद्धाओं ने सत्ता की नींव हिला दी। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने न्यायालय के एक निर्णय के विरुद्ध पूरे देश पर आतंकवादी थोप दिया, तो जयप्रकाश नारायण ने ऐसा प्रयत्नकारी आंदोलन खड़ा किया कि कांग्रेस की सत्ता जग से उखड़ गई। इस आंदोलन में कांग्रेस छोड़कर आए विषय के अनेक प्रमुख नेता शामिल हुए। इन्होंने आचार्य जे.बी. कृपालनी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चरण सिंह, जॉर्ज फर्नान्डिस, मधु सिंघर, राज नारायण, कर्पूरी ठाकुर, विश्व जोशी, दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायी और भी कई दिग्गज थे। इन सबने जयप्रकाश के नेतृत्व में एकजुट होकर तानाशाही के विरुद्ध जनसंख्यक खंड कर दिया। यह बटना भले ही घघास वर्ष पुरानी हो, किंतु इसके सगन अनेक आंदोलनों में देश की राजनीतिक चेतना में देखा दी है। लेकिन विषय के कि आज जब कांग्रेस और विषय के अन्य नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी से सत्ता हथियाने का आरोप लगा रहा है, तब बीजेपी विधेयी नेतृत्व में 'शो मचाने' की बयाप जनता को संगठित कर आंदोलन मुम्बू नहीं खड़ा कर रहे हैं? क्या विषय में जयप्रकाश जैसा कोई नायक नहीं है? या फिर जनता जनता पार्टी को देश की जनता उसकी विचारधारा के चलते हाथों हाथ ले रही है। इसी का परिणाम है पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार का आना और असम में बीजेपी का ऐतिहासिक लाना। बीजेपी की इस जीत को सत्य हथियाने की वोट चोरी बता रहा है।



जयप्रकाश का आंदोलन अकेला नहीं था। भारत ने ब्रह्मचर्य ब्रज जन आक्रोश देखा है जो सत्ताधियों को बुझने पर मजबूर कर गया। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद सत्ता के विरुद्ध वी.पी. सिंह सरकार के विरुद्ध लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, यह राम जयलक्ष्मी आंदोलन का रूप ले लिया। लालू कारसेक अयोध्या पहुंचे। इससे भाजपा मजबूत हुई और सरकार गिरी। 2011 में अना हत्यारे ने प्रचाराय के विरुद्ध राखौली मैदान में अग्रगण्य किया। पार्टी बनी और मोरारजी देसाई प्र-पानम्नी। जयप्रकाश का आंदोलन विरुद्ध करत है कि जनसक्ति सत्ता को घुटाने पर ला सकती है। अथ ऐतिहासिक आंदोलन

जयप्रकाश का आंदोलन अकेला नहीं था। भारत ने ब्रह्मचर्य ब्रज जन आक्रोश देखा है जो सत्ताधियों को बुझने पर मजबूर कर गया। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद सत्ता के विरुद्ध वी.पी. सिंह सरकार के विरुद्ध लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, यह राम जयलक्ष्मी आंदोलन का रूप ले लिया। लालू कारसेक अयोध्या पहुंचे। इससे भाजपा मजबूत हुई और सरकार गिरी। 2011 में अना हत्यारे ने प्रचाराय के विरुद्ध राखौली मैदान में अग्रगण्य किया। पार्टी बनी और मोरारजी देसाई प्र-पानम्नी। जयप्रकाश का आंदोलन विरुद्ध करत है कि जनसक्ति सत्ता को घुटाने पर ला सकती है। अथ ऐतिहासिक आंदोलन

भारत माता की पैतृहसिक विद्रोह भारत माता की पैतृहसिक विद्रोह भारत माता की पैतृहसिक विद्रोह... (Text is repetitive and partially obscured)

